



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 11, 2018/आश्विन 19, 1940

No. 381]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2018/ASVINA 19, 1940

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2018

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2018**

सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.033.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 199, धारा 200, धारा 201, धारा 203 और धारा 204 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में, विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“3. रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता –** (1) कोई भी व्यक्ति दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी नहीं है, और –

(क) उसका एकमात्र उद्देश्य संहिता के अधीन किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के कृत्यों का निर्वहन करना है;

(ख) उसकी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 के अनुसार उप-विधियां और संचालन ढांचा है;

(ग) उसका कुल मूल्य कम से कम दस करोड़ रुपए है;

(घ) उसकी समादत्त शेयर पूंजी पांच करोड़ रुपए है;

(ङ) वह भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति के नियंत्रणाधीन नहीं है;

(च) उसकी उनचास प्रतिशत से अनधिक शेयर पूंजी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत के बाहर निवासी किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित नहीं है;

(छ) वह एक से अधिक स्तर पर किसी निगमित निकाय की समनुषंगी नहीं है; और

(ज) आवेदक, उसके संप्रवर्तक, उसके निदेशक और उसके शेयरधारक उपयुक्त और समुचित व्यक्ति हैं।

**स्पष्टीकरण 1**—खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, किसी निगमित निकाय के संबंध में “स्तर” पद से उसकी समनुषंगी अभिप्रेत है।

**स्पष्टीकरण 2**—बोर्ड, इस बात का अवधारण करने के लिए कि कोई व्यक्ति खंड (ज) के अधीन उपयुक्त और समुचित है अथवा नहीं, किसी भी ऐसी विचारणा को ध्यान में रख सकेगा, जो वह उचित समझे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मानदंड आता है किन्तु यही तक सीमित नहीं है —

(i) सत्यनिष्ठा, ख्याति और चरित्र,

(ii) दोषसिद्धि और अवरोध आदेशों का न होना, और

(iii) सक्षमता, जिसके अंतर्गत वित्तीय शोधन क्षमता और कुल मूल्य है।

(2) कोई व्यक्ति, किसी भी समय व्यक्ति रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की पांच प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी अर्जित या धारित नहीं करेगा।

परन्तु —

(i) कोई स्टॉक एक्सचेंज;

(ii) कोई निक्षेपधारी;

(iii) कोई बैंकिंग कंपनी;

(iv) कोई बीमा कंपनी;

(v) कोई लोक वित्तीय संस्था; और

(vi) कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्था,

व्यष्टिक रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की पन्द्रह प्रतिशत तक समादत्त साधारण शेयर पूंजी अर्जित या धारित कर सकेगी:

परन्तु यह और कि —

(i) केन्द्रीय सरकार;

(ii) कोई राज्य सरकार; और

(iii) कोई कानूनी विनियामक,

किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः शत-प्रतिशत तक समादत्त साधारण शेयर पूंजी अर्जित या धारित कर सकेगा।

3. मूल विनियमों की अनुसूची में, प्ररूप क के अनुलग्नक के भाग 3 में,-

(क) खंड 8 में, 10% के स्थान पर 5% रखा जाएगा;

(ख) खंड 13 में, 10% के स्थान पर 5% रखा जाएगा ।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./305/18]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 420, तारीख 21 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.002, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2018

#### INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

**No. IBBI/2018-19/GN/REG33.**—In exercise of the powers conferred by sections 196, 199, 200, 201, 203, 204 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely: -

**1.** (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely: -

**“3. Eligibility for registration.** - (1) No person shall be eligible for registration as an insolvency professional agency unless it is a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013, and -

- (a) its sole object is to carry on the functions of an insolvency professional agency under the Code;
- (b) it has bye-laws and governance structure in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016;
- (c) it has a minimum net worth of ten crore rupees;
- (d) it has a paid-up share capital of five crore rupees;
- (e) it is not under the control of any person resident outside India;
- (f) not more than forty-nine per cent. of its share capital is held, directly or indirectly, by persons resident outside India;
- (g) it is not a subsidiary of a body corporate through more than one layer; and
- (h) the applicant, its promoters, its directors and its shareholders are fit and proper persons.

*Explanation 1.* - For the purposes of clause (g), “layer” in relation to a body corporate means its subsidiary.

*Explanation 2.* - For determining whether a person is fit and proper under clause (h), the Board may take into account any consideration as it deems fit, including but not limited to the following criteria, namely: -

- (i) integrity, reputation and character,
- (ii) absence of conviction and restraint orders,
- (iii) competence including financial solvency and net worth.

(2) No person shall at any time, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than five per cent. of the paid-up equity share capital in an insolvency professional agency:

Provided that-

- (i) a stock exchange;
- (ii) a depository;
- (iii) a banking company;
- (iv) an insurance company;
- (v) a public financial institution; and
- (vi) a multilateral financial institution,

may, acquire or hold, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, up to fifteen per cent. of the paid-up equity share capital of an insolvency professional agency:

Provided further that-

- (i) the Central Government;
- (ii) a State Government; and
- (iii) a statutory regulator,

may, acquire or hold, directly or indirectly, up to hundred per cent. of the paid-up equity share capital of an insolvency professional agency.”.

**3.** In the principal regulations, in the Schedule, in Annexure to Form A, in Part III, -

- (a) in clause 8, for “10%”, “5%” shall be substituted;
- (b) in clause 13, for “10%”, “5%” shall be substituted.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./305/18]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG002 on 22<sup>nd</sup> November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 420 dated 21<sup>st</sup> November, 2016 and these have not been amended so far.